

DAILY CURRENT AFFAIRS

By



SOURCES



Date: 3-4 Apr. 2024

Important News Articles

1. दक्षिण एशिया, भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश नष्ट होने का जोखिम: विश्व बैंक -द हिंदू
2. ED 'किसी भी जानकारी' के लिए किसी को भी समन कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट- द हिंदू
3. चुनावी बॉन्ड: कंपनियों ने अपने मुनाफ़े से कहीं ज़्यादा दान दिया - द हिंदू
4. सुप्रीम कोर्ट एकतरफा तलाक पर केरल हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करेगा -इंडिया टुडे
5. परमाणु ऊर्जा भारत के विकास की कुंजी है: IIM अहमदाबाद रिपोर्ट -द हिंदू
6. सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु ने केंद्र पर आपदा राहत कोष में देरी का आरोप लगाया- द हिंदू
7. भारत ने झींगा हैचरी में एब्यूसिव स्थितियों पर रिपोर्ट को खारिज किया - द हिंदू
8. सरकार ने 'ग्रीन स्टील' के लिए 13 टास्क फोर्स को मंजूरी दी - द हिंदू

Editorials, Gists and Explainers

9. भारत और श्रीलंका के बीच कच्चाथीवू द्वीप विवाद - द हिंदू
10. राज्यों की उधार लेने की शक्तियों पर केरल-केंद्र विवाद - द हिंदू

Quick Look

1. व्हाइट रैबिट (WR)
2. लम्पी स्किन डिजीज
3. न्यायालय की अवमानना
4. जापान सागर
5. पुनेट स्कायर

महत्वपूर्ण समाचार लेख

सामान्य अध्ययन ।

1. दक्षिण एशिया, भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश नष्ट होने का जोखिम: विश्व बैंक -द हिंदू

प्रासंगिकता: महिलाओं और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके समाधान।

समाचार:

- विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि भारत सहित दक्षिण एशिया क्षेत्र अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग नहीं कर रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार सृजन की गति बढ़ रही है।
- इससे कामकाजी उम्र की आबादी में वृद्धि कम हो जाएगी, भले ही उसने अपने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय अपडेट, जॉब्स फॉर रेजिलिएंस में इस क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 के लिए 6.0-6.1% की मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाया था।

प्रीलिम्स टेकअवे

- जनसांख्यिकीय विभाजन
- TFR

मुख्य बिंदु

- यह देखते हुए कि वर्ष 2000-23 की अवधि में भारत की रोजगार वृद्धि इसकी कामकाजी आयु आबादी में औसत वृद्धि से काफी नीचे थी
- बहुपक्षीय ऋणदाता ने कहा कि परिणामस्वरूप वर्ष 2022 तक नेपाल को छोड़कर क्षेत्र के किसी भी अन्य देश की तुलना में देश के रोजगार अनुपात में अधिक गिरावट आई है।
- यह देखते हुए कि भारत की अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2013/24 में 7.5% की "मजबूत वृद्धि" दर्ज करने की उम्मीद थी, ऋणदाता ने कहा कि श्रीलंका और पाकिस्तान में रिकवरी के साथ यह वृद्धि, बड़े पैमाने पर दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए मजबूत संख्या को बढ़ा रही थी।
- फिर भी, इस क्षेत्र में 16% अधिक उत्पादन वृद्धि हो सकती है यदि इसकी कामकाजी उम्र की आबादी का हिस्सा जो कार्यरत था वह अन्य EMDE के बराबर था
- दक्षिण एशिया अभी अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरी तरह से लाभ उठाने में विफल हो रहा है, यह एक चूक गया अवसर है
- क्षेत्र में कमजोर रोजगार रुझान गैर-कृषि क्षेत्रों में केंद्रित थे
- नौकरी में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ने अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन करने, व्यापार में खुलापन बढ़ाने और शिक्षा में सुधार करने की सिफारिश की है।

जनसांख्यिकीय विभाजन

- जैसा कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) द्वारा परिभाषित किया गया है, यह "आर्थिक विकास क्षमता है जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप हो सकती है, मुख्य रूप से जब कामकाजी उम्र की आबादी (15 से 64) का हिस्सा आबादी के गैर-कामकाजी उम्र के हिस्से (14 और उससे कम उम्र, और 65 और उससे अधिक उम्र) से बड़ा होता है

भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति और चुनौतियाँ

- लैंसेट रिपोर्ट एक संदेश है कि भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश हमेशा के लिए नहीं है।
- वैश्विक अनुभव देश के नीति निर्माताओं के लिए उदाहरण हो सकते हैं।
- उदाहरण के लिए, चीन में, कामकाजी उम्र की आबादी का अनुपात वर्ष 1987 में 50 प्रतिशत को पार कर गया और पिछले दशक के मध्य में अपने चरम पर पहुंच गया।
- यही वह अवधि थी जब देश ने प्रभावशाली आर्थिक विकास दर्ज किया था।
- पिछले साल तक, चीन की TFR रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई थी और इसकी कामकाजी उम्र की आबादी में 40 मिलियन से अधिक की कमी आई थी।

- चीनी सरकार के जनसंख्या-वृद्धि समर्थक उपाय काम करते नहीं दिख रहे हैं।
- वास्तव में, **विकसित देशों** के पिछले **60 वर्षों** के इतिहास से पता चलता है कि एक बार **प्रजनन दर** प्रतिस्थापन दर से नीचे आ जाए, तो उसे वापस स्थापित करना लगभग असंभव है।
- 1.9 पर, भारत का **TFR वर्तमान** में **प्रतिस्थापन दर** से ठीक नीचे है, और **UNPF** गणना के अनुसार, देश की कामकाजी आयु की आबादी का हिस्सा **वर्ष 2030** के अंत में, **वर्ष 2040** के दशक की शुरुआत में चरम पर होगा।
- इसलिए, नीति निर्माताओं को **भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश** को अधिकतम करने के लिए इस **विंडो** का उपयोग करना चाहिए, जैसा कि **चीन** ने **वर्ष 1980** के दशक के अंत से लेकर पिछले दशक के शुरुआती वर्षों तक किया था।
- कौशल की कमी को दूर करने और **ज्ञान अर्थव्यवस्था** में कमियों को दूर करने के उपाय करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए।
- चुनौती कृषि के बाहर **नौकरियां पैदा** करने की भी होगी, वे कम वेतन वाले **अनौपचारिक क्षेत्र** में नहीं होनी चाहिए।
- आगे बढ़ते हुए, नीति निर्माताओं को बढ़ती बुजुर्ग आबादी के लिए पर्याप्त **सामाजिक सुरक्षा** और **स्वास्थ्य** देखभाल प्रावधान भी सुनिश्चित करने होंगे और उनके **कौशल** का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के अवसर प्रदान करने होंगे।

सामान्य अध्ययन II

2. ED 'किसी भी जानकारी' के लिए किसी को भी समन कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट- द हिंदू

प्रासंगिकता: वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।

समाचार:

- **सुप्रीम कोर्ट** ने **प्रवर्तन निदेशालय (ED)** की व्यापक शक्तियों का समर्थन किया
- इसमें कहा गया है कि **केंद्रीय एजेंसी** "किसी भी जानकारी के लिए किसी को भी बुला सकती है" हालांकि उसने **तमिलनाडु** के **चार जिला कलेक्टरों** को **मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निकाय** द्वारा जारी किए गए समन के जवाब में **व्यक्तिगत रूप** से उपस्थित होने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई।

प्रीलिम्स टेकअवे

- प्रवर्तन निदेशालय
- FERA

PMLA की धारा 50(2)

- इसने **ED** को "**किसी भी व्यक्ति**" को बुलाने का अधिकार दिया, जिसकी उपस्थिति कानून के तहत "**किसी भी जांच या कार्यवाही**" के दौरान साक्ष्य देने या रिकॉर्ड पेश करने के लिए आवश्यक मानी जाती थी।

धारा 50(3)

- यह अनिवार्य है कि बुलाया गया व्यक्ति "**व्यक्तिगत रूप** से या **अधिकृत एजेंटों** के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बाध्य है" और उसे सच्चे बयान देने और आवश्यक दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता होगी।

प्रवर्तन निदेशालय (ED)

- **प्रवर्तन निदेशालय (ED)** एक **बहु-विषयक संगठन** है जिसे **मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों** के उल्लंघन की जांच का अधिकार है।
- यह **वित्त मंत्रालय** के **राजस्व विभाग** के अंतर्गत कार्य करता है।
- इस **निदेशालय** की उत्पत्ति **1 मई, 1956** से हुई, जब **विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA), 1947** के तहत **विनियमन नियंत्रण कानूनों** के उल्लंघन से निपटने के लिए **आर्थिक मामलों** के विभाग में एक '**प्रवर्तन इकाई**' का गठन किया गया था।
- इसका **मुख्यालय दिल्ली** में था, जिसका **नेतृत्व प्रवर्तन निदेशक** के रूप में एक **कानूनी सेवा अधिकारी** करता था।
- इसकी **बम्बई और कलकत्ता** में दो शाखाएँ थीं।

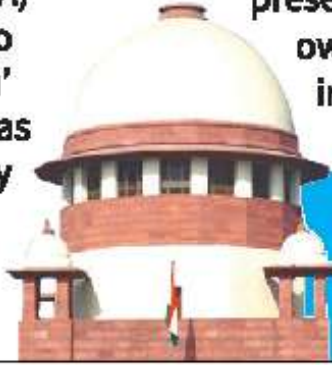
Sharp censure

SC reprimands District Collectors of Vellore, Ariyalur, Karur and Tiruchi in T.N. for not appearing before investigative agency

■ Bench states that Section 50(2) of Prevention of Money Laundering Act (PMLA) empowered the ED to summon 'any person' whose attendance was considered necessary for giving evidence or production of records

■ District Collectors express inability to compile data and present it to ED on time owing to poll work and implementation of welfare programmes

■ Bench refuses to accept argument; lists case for May 6



3. चुनावी बॉन्ड: कंपनियों ने अपने मुनाफ़े से कहीं ज़्यादा दान दिया - द हिंदू

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

समाचार:

- 12 अप्रैल, 2019 और 24 जनवरी, 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड के खरीदारों और भुनाने वालों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 45 कंपनियों, जिन्होंने ऐसे बॉन्ड के माध्यम से ₹1,432.4 करोड़ का कुल दान दिया था, उनके पास धन के संदिग्ध स्रोत थे।

चुनावी बॉन्ड :

- चुनावी बॉन्ड वचन पत्र की तरह धन उपकरण हैं, जिन्हें भारत में कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से खरीदा जा सकता है और एक राजनीतिक दल को दान दिया जा सकता है, जो बाद में इन बॉन्डों को भुना सकता है।
- बॉन्ड केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में ही भुनाए जा सकते हैं।
- एक व्यक्ति व्यक्तिगत होने के नाते अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बॉन्ड खरीद सकता है।

चुनावी बॉन्ड के पक्ष में तर्क

- दानदाताओं की गोपनीयता की रक्षा करने से राजनीतिक प्रतिशोध की आशंका भी काफी कम हो जायेगी
- अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत सूचना का अधिकार केवल अनुच्छेद 19(2) में सूचीबद्ध आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, जिसमें काले धन पर अंकुश लगाने का उद्देश्य शामिल नहीं है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29C

- वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा संशोधित होने से पहले, सभी राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से अधिक के किसी भी योगदान की घोषणा करने की आवश्यकता थी।
- धारा में संशोधन, जिसने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त दान के लिए घोषणा करने से छूट दी थी, अदालत ने खारिज कर दिया था।

प्रीलिम्स टेकअवे

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
- चुनावी बॉन्ड

4. सुप्रीम कोर्ट एकतरफा तलाक पर केरल हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करेगा -इंडिया टुडे

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

समाचार:

- सुप्रीम कोर्ट **केरल हाई कोर्ट** के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें **मुस्लिम महिलाओं** को 'खुला' के जरिए तलाक लेने का पूरा अधिकार दिया गया था।
- इस्लामी कानून विवाह समाप्त करने के **खुला और तलाक** दो मुख्य तरीके प्रदान करता है।

खुला: तलाक शुरू करने का एक महिला का अधिकार

- कुरान में उल्लिखित खुला, महिलाओं को अदालत में अपने पतियों से अलग होने की मांग करने का अधिकार देता है।
- दुरुपयोग, उपेक्षा या बस असंगत होने जैसे वैध कारणों का हवाला दिया जा सकता है।
- समझौते के तहत पत्नी अपना दहेज (मेहर) वापस कर सकती है।
- खास बात यह है कि खुला तलाक के बाद बच्चे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी पति पर ही रहती है।

तलाक: तलाक की पहल पति द्वारा की जाती है

- इसके विपरीत, तलाक पतियों को अदालत की मंजूरी या कारण बताए बिना अपनी पत्नी को तलाक देने का अधिकार देता है।
- जबकि दहेज और पत्नी के स्वामित्व वाली कोई भी संपत्ति वापस की जानी चाहिए, यह प्रक्रिया कम संरचित है।
- यह प्रणाली दोनों पति-पत्नी को एक नाखुश विवाह को समाप्त करने की क्षमता देती है, लेकिन खुला महिलाओं को अधिक नियंत्रण देती है और प्रक्रिया के दौरान उनके अधिकारों की रक्षा करती है।

प्रीलिम्स टेकअवे

- तलाक
- खुला

सामान्य अध्ययन III

5. परमाणु ऊर्जा भारत के विकास की कुंजी है: IIM अहमदाबाद रिपोर्ट -द हिंदू

प्रासंगिकता: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि।

समाचार:

- भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित देश बनाने और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य या प्रभावी रूप से शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन** हासिल करने की राह पर होना।
- IIM, अहमदाबाद के शिक्षाविदों** के एक अध्ययन में कहा गया है कि इसे परमाणु ऊर्जा में निवेश को महत्वपूर्ण रूप से प्राथमिकता देनी चाहिए और संबंधित बुनियादी ढांचे का विस्तार करना चाहिए।

मुख्य बिंदु

- परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, इसका मतलब है कि वर्ष 2030 तक **भारत की कुल ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का योगदान 4% होगा और वर्ष 2050 तक तेजी से बढ़कर 30% हो जाएगा।**
- इसी परिदृश्य में, **सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2030 में 42% से गिरकर वर्ष 2050 में 30% हो जाती है।**

यूरेनियम उपलब्धता

- वर्तमान में, **केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण** के आंकड़े कहते हैं कि **भारत की स्थापित उत्पादन क्षमता में सौर ऊर्जा का हिस्सा 16% और कोयले का 49% है।**
- परमाणु ऊर्जा** के लिए इन **आदर्शवादी आंकड़ों** को प्राप्त करने के लिए निवेश के साथ-साथ **यूरेनियम** की धारणा को दोगुना करने की आवश्यकता होगी
- एक महत्वपूर्ण ईंधन, लेकिन **अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध** द्वारा प्रतिबंधित, आवश्यक मात्रा में उपलब्ध है।
- कोयला संभवतः **भारतीय ऊर्जा प्रणाली की "बैकबॉन"** होगा और अगर देश को अगले **तीन दशकों** में कोयले को चरणबद्ध तरीके से बंद करना होगा

प्रीलिम्स टेकअवे

- यूरेनियम
- नाभिकीय विखंडन
- बैकबॉन

- नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण का समर्थन करने के लिए लचीले ग्रिड बुनियादी ढांचे और भंडारण के अलावा, परमाणु ऊर्जा जैसे वैकल्पिक स्रोतों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की आवश्यकता होगी।

6. सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु ने केंद्र पर आपदा राहत कोष में देरी का आरोप लगाया- द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

समाचार:

- तमिलनाडु ने मुख्यमंत्री द्वारा मांगे गए लगभग ₹38,000 करोड़ के आपदा राहत कोष को जारी करने में देरी करके केंद्र सरकार पर राज्य के लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया।

मुख्य बिंदु

- इसका उद्देश्य चक्रवात मिचौंग और अप्रत्याशित बाढ़ की दोहरी आपदाओं से निपटने में मदद करना है।
- तमिलनाडु का मुकदमा उच्चतम न्यायालय में केरल और कर्नाटक के हालिया मुकदमे के बाद आता है।
- केरल ने केंद्र पर उसकी नेट बोर्रोविंग लिमिटेड में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है, जिससे राज्य वित्तीय आपातकाल के कगार पर पहुंच गया है।
- कर्नाटक ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत सूखा राहत जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष

- वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के अधिनियमन के साथ राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (NCCF) का नाम बदलकर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (NDRF) कर दिया गया।
- इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (DM Act) की धारा 46 में परिभाषित किया गया है।
- इसे भारत सरकार के "सार्वजनिक खाते" में "ब्याज रहित आरक्षित निधि" के अंतर्गत रखा जाता है।

पब्लिक अकाउंट:

- इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत किया गया था।
- यह उन लेनदेन के लिए प्रवाह का हिसाब रखता है जहां सरकार केवल एक बैंकर के रूप में कार्य कर रही है जैसे भविष्य निधि, छोटी बचत आदि।
- ये धनराशि सरकार की नहीं है और इन्हें कुछ समय पर वापस भुगतान करना होगा।
- इससे होने वाले व्यय को संसद द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता नहीं है।

चक्रवात मिचौंग

- चक्रवात दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाले क्षेत्र से विकसित हुआ।
- यह धीरे-धीरे एक गहरे अवसाद, एक चक्रवाती तूफान और अंत में एक सुपर-चक्रवात तूफान में तब्दील हो गया।
- उन्हें समुद्र की सतह के गर्म तापमान और मैडेन-जूलियन दोलन से सहायता मिली, जो मौसम की एक विसंगति है जो वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करती है।
- यह उत्तर की ओर आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ गया, जबकि उत्तरी तमिलनाडु में भारी बारिश और तेज़ हवाएँ आईं।
- इसने बापटला जिले के पास भूस्खलन किया, और भूमि पर एक अवसाद के रूप में कमजोर हो गया।
- विश्व मेट्रोलॉजिकल संगठन और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा तैयार किए गए नामों की सूची के बाद म्यांमार द्वारा मिचौंग नाम का सुझाव दिया गया था जो ताकत और लचीलेपन का प्रतीक है।

7. भारत ने झींगा हैचरी में एब्यूसिव स्थितियों पर रिपोर्ट को खारिज किया - द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

समाचार:

- अमेरिका के पसंदीदा समुद्री भोजन झींगा के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता भारत ने शिकागो स्थित मानवाधिकार समूह द्वारा लगाए गए मानवाधिकारों और पर्यावरण के दुरुपयोग के आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया है।

प्रीलिम्स टेकअवे

- मिचौंग
- चक्रवात

मुख्य बिंदु

- वर्ष 2022-23 में, भारत का समुद्री भोजन निर्यात \$8.09 बिलियन या ₹64,000 करोड़ रहा, और इन निर्यातों में झींगा की हिस्सेदारी \$5.6 बिलियन थी।
- भारत दुनिया के सबसे बड़े झींगा निर्यातकों में से एक के रूप में उभरा है और अमेरिकी बाजार में इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 में 21% से बढ़कर 40% हो गई है, जो थाईलैंड, चीन, वियतनाम और इक्वाडोर जैसे प्रतिद्वंद्वियों से कहीं आगे है।
- भारत के झींगा निर्यात के लिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित है और विदेशी शिपमेंट के बारे में ऐसी चिंताओं की कोई गुंजाइश नहीं है।
- राज्य: अकेले आंध्र प्रदेश में लगभग एक लाख झींगा फार्म भारत के झींगा उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा हैं।
- महिलाओं की भागीदारी : माना जाता है कि इस क्षेत्र में लगभग 80 लाख नौकरियों में से 70% महिलाएं हैं, जिनमें से दो लाख हैचरी और एक्काकल्चर फार्म में हैं, और बाकी प्रसंस्करण और प्रीजिंग इकाइयों में हैं।
- मंत्रालय अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख बाजारों में चिंताओं को दूर करने के लिए निर्यातकों को झींगा फार्मों में काम करने की स्थितियों पर स्वतंत्र अध्ययन कराने की सलाह दे सकता है।

SAIME पहल

- सस्टेनेबल एक्काकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम (SAIME) पहल के तहत, किसानों ने पश्चिम बंगाल में 30 हेक्टेयर में झींगा की खेती शुरू की है।
- मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को झींगा की खेती के साथ एकीकृत किया गया है, लेकिन जब मत्स्य पालन का अंदर की ओर विस्तार किया गया, तो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को बाहर कर दिया गया।
- मछली पकड़ना, विशेष रूप से झींगा पालन, सुंदरबन के लोगों के प्रमुख व्यवसायों में से एक है, जो नदियों और निचले द्वीपों का एक जटिल नेटवर्क है जो दिन में दो बार ज्वार की लहर का सामना करता है।

8. सरकार ने 'ग्रीन स्टील' के लिए 13 टास्क फोर्स को मंजूरी दी - द हिंदू

प्रासंगिकता: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि।

समाचार:

- केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री ने 'ग्रीन स्टील' के रोडमैप को परिभाषित करने के लिए 13 टास्क फोर्स को मंजूरी दी है।
- विशेषज्ञों और उद्योग हितधारकों की भागीदारी के साथ टास्क फोर्स की पहचान 'ग्रीन स्टील' उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने और कार्रवाई बिंदु तैयार करने के लिए की गई है।

प्रीलिम्स टेकअवे

- राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन
- ग्रीन स्टील

मुख्य बिंदु

- 'ग्रीन स्टील' के लिए टास्क फोर्स शब्दावली, परिभाषा, बेंचमार्क, स्कोपिंग, प्रमाणन और अन्य सहित ग्रीन स्टील की वर्गीकरण विकसित करने पर काम करेगी।
- "इस्पात संयंत्रों के कार्बन उत्सर्जन की निगरानी" के लिए टास्क फोर्स कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की निगरानी के लिए मानक तैयार करने और निगरानी के लिए कार्यप्रणाली और संस्थागत तंत्र के विकास पर काम करेगी।
- डिमांड साइड टास्कफोर्स प्रमुख अंतिम-उपयोग क्षेत्रों में हरित इस्पात की मांग पैदा करने के लिए एक नीतिगत ढांचा बनाएगी।
- आपूर्ति पक्ष कार्यबल ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण, सामग्री दक्षता, हरित हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण, और प्रक्रिया संक्रमण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- RD&D जैसे फैसिलिटेटर का कार्यबल भारत में इस्पात क्षेत्र के हरित परिवर्तन के लिए एक शोध रोडमैप तैयार करेगा।
- अंतर्राष्ट्रीय फोकस समूह हरित इस्पात उत्पादन के लिए दुनिया भर में किए जा रहे उपायों की पहचान करेगा और उनका मिलान करेगा और संभावित सहयोग का पता लगाएगा।
- RINL विशाखापत्तनम स्टील प्लांट GHG उत्सर्जन और ऊर्जा खपत को कम करने के लिए अत्याधुनिक क्लीनर प्रौद्योगिकियों को स्थापित करने में अग्रणी रहा है।
- अपशिष्ट ऊष्मा से विद्युत उत्पादन कुल कैप्टिव विद्युत उत्पादन का लगभग 62% है।
- 'प्रत्येक टन इस्पात क्षमता के लिए एक पेड़' के आदर्श वाक्य के साथ, 5 मिलियन से अधिक पेड़ लगाए गए हैं

ग्रीन स्टील

- यह **जीवाश्म ईंधन** के उपयोग के बिना स्टील का विनिर्माण है।
- यह **कोयला आधारित संयंत्रों** के **पारंपरिक कार्बन-सघन विनिर्माण मार्ग** के बजाय **हाइड्रोजन, कोयला गैसीकरण**, या बिजली जैसे कम **कार्बन ऊर्जा स्रोतों** का उपयोग करके किया जा सकता है।
- यह अंततः **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** को कम करता है, लागत में कटौती करता है और स्टील की गुणवत्ता में सुधार करता है।
- निम्न-कार्बन हाइड्रोजन (नीला हाइड्रोजन और हरा हाइड्रोजन) **इस्पात उद्योग** के कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद कर सकता है।
- राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन (NHM) स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन विकल्प के लिए हाइड्रोजन का उपयोग करता है

एडिटोरियल, जिस्ट, एक्सप्लेनेर

9. भारत और श्रीलंका के बीच कच्चाथीवू द्वीप विवाद - द हिंदू

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है और/या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं।

समाचार:

- तमिलनाडु में **लोकसभा चुनाव** से कुछ हफ्ते पहले **प्रधानमंत्री** ने **कच्चाथीवू** का विवादित मामला फिर उठाया।

कच्चाथीवू श्रीलंका का हिस्सा कब बना?

- 26-28 जून, 1974 के दौरान, भारत और श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों, इंदिरा गांधी और सिरिमा आरडी भंडारनायके ने पाक जलडमरूमध्य से एडम ब्रिज तक ऐतिहासिक जल में दोनों देशों के बीच सीमा का सीमांकन करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- इसमें यह भी बताया गया है कि "यह सीमा निर्जन कच्चाथीवू के पश्चिमी तट से एक मील दूर पड़ती है।"
- इस समझौते के कारण अक्टूबर 1921 से दोनों पक्षों के बीच चल रही वार्ता समाप्त हो गई। प्रारंभ में, वार्ता तत्कालीन मद्रास और सीलोन की सरकारों के बीच आयोजित की गई थी।

मछुआरों के लिए कच्चाथीवू कितना महत्वपूर्ण रहा है?

- दोनों देशों के मछुआरे परंपरागत रूप से मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप का उपयोग करते रहे हैं।
- हालाँकि इस फ़्रीचर को वर्ष 1974 के समझौते में स्वीकार किया गया था, मार्च 1976 में पूरक समझौते ने इसे स्पष्ट कर दिया
 - दोनों देशों के मछली पकड़ने वाले जहाज और मछुआरे "श्रीलंका या भारत की स्पष्ट अनुमति के बिना" किसी भी देश के ऐतिहासिक जल, क्षेत्रीय समुद्र और विशेष क्षेत्र या विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने में "शामिल नहीं होंगे"।

भारत और श्रीलंका के बीच बातचीत की शुरुआत किस वजह से हुई?

- श्रीलंका ने इस आधार पर काचाथिवु पर संप्रभुता का दावा किया कि वर्ष 1505-1658 ई. के दौरान द्वीप पर कब्जा करने वाले पुर्तगालियों ने इस द्वीप पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया था।
- भारत का तर्क यह था कि रामनाड [रामनाथपुरम] के तत्कालीन राजा ने अपनी जमीन के हिस्से के रूप में इस पर कब्जा कर लिया था।

वर्ष 1974 का समझौता कैसे प्राप्त हुआ?

- कच्चाथीवू पुनर्प्राप्ति की वर्तमान मांग की उत्पत्ति 1974 में उत्पन्न संधि के विरोध से हुई है।

इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का क्या रुख रहा है?

- अगस्त 2013 में, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि **टापू ब्रिटिश भारत और सीलोन** (अब श्रीलंका) के बीच विवाद का मामला था और इसकी कोई सहमत सीमा नहीं थी, जिसका मामला **वर्ष 1974** और **वर्ष 1976** के समझौतों के माध्यम से सुलझाया गया था।

- दिसंबर 2022 में, केंद्र सरकार ने दो समझौतों का जिक्र करते हुए, राज्यसभा में अपने जवाब में बताया कि कच्चातिलु "भारत-श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के श्रीलंकाई पक्ष पर स्थित है।
- इसमें कहा गया कि मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

10. राज्यों की उधार लेने की शक्तियों पर केरल-केंद्र विवाद - द हिंदू

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका।

समाचार:

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केरल द्वारा दायर एक मुकदमे को संविधान पीठ के पास भेजने का आदेश, जिसमें केंद्र के उसकी उधारी में कटौती के फैसले को चुनौती दी गई थी, एक स्वागत योग्य घटनाक्रम है।
- न्यायालय ने केंद्र द्वारा उधार सीमा लागू करने से पहले की स्थिति बहाल करने के लिए अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया
- रेफरल एक बड़ी बेंच को यह जांचने का मौका देगा कि केंद्र सरकार किसी राज्य की उधारी को किस हद तक नियंत्रित कर सकती है।

मुख्य बिंदु

- यह मुकदमा राज्य में वाम मोर्चा शासन के खिलाफ केंद्र के राजकोषीय कुप्रबंधन के आरोप पर झगड़े से कहीं अधिक है।
- न्यायालय ने माना है कि यह केंद्र-राज्य संबंधों पर भी एक संवैधानिक प्रश्न है:
 - एक ओर देश के वित्तीय स्वास्थ्य को बनाए रखने के प्रयासों के बीच एक स्पष्ट संघर्ष है और दूसरी ओर राज्यों की वित्तीय स्थिति को कमजोर करने वाले कदम हैं।

अनुच्छेद 293

- इस विवाद के केंद्र में अनुच्छेद 293 है, जो राज्यों को राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर धन उधार लेने की कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है।
- यह संघ को राज्यों को ऋण और गारंटी देने की भी अनुमति देता है, और केंद्र को अपनी सहमति देने और राज्यों पर आगे ऋण जुटाने के लिए शर्तें लगाने की आवश्यकता होती है, जबकि पहले के ऋण बकाया हैं।
- केरल का तर्क है कि यह अनुच्छेद केंद्र को सभी राज्य ऋणों को विनियमित करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है और यह केवल केंद्र से उधार लेने पर शर्तें लगा सकता है।
- केरल ने राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा उधार लेने और अपने सार्वजनिक खाते पर देनदारियों को 'नेट उधार सीमा' के तहत शामिल करने के केंद्र के फैसले को भी चुनौती दी है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम

- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में वर्ष 2018 के संशोधन ने 'सामान्य सरकारी ऋण', या केंद्र और राज्य सरकारों के ऋणों का कुल योग, सकल घरेलू उत्पाद के 60% पर सीमित कर दिया।
- केंद्र सरकार का तर्क है कि सार्वजनिक वित्त एक राष्ट्रीय मुद्दा है, वह उधार लेने की सीमा को दरकिनार करने के लिए ऑफ-बजट उधार के उपयोग को रोकना चाहती थी।
- इसमें यह भी दावा किया गया है कि राज्य सरकारों द्वारा असीमित उधार लेने से उधार लेने की लागत बढ़ जाएगी और निजी क्षेत्र के उधारकर्ता बाहर हो जाएंगे।
- यह मुद्दा ऐसे समय में आया है जब राजस्व वितरण के मौजूदा फॉर्मूले को ऐसे राज्यों के रूप में देखा जा रहा है जो सामाजिक संकेतकों पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को दंडित करते हैं।
- यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सामाजिक उन्नति में अग्रणी केरल को इस संकट का सामना करना पड़ रहा है।
- ऐसे युग में जब राज्यों के लिए एक प्रमुख राजस्व स्रोत को एक ऐसी प्रणाली में शामिल कर लिया गया है जिसमें वे केंद्र के साथ एक सामान्य वस्तु और सेवा कर की आय साझा करते हैं, राजकोषीय गुंजाइश कीमती हो गई है।
- अब यह सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर है कि वह यह निर्धारित करे कि केंद्र को उधार लेने की सीमा पर कितना सख्त होना चाहिए और संघीय मानदंडों का उल्लंघन किए बिना राज्यों को उनके वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए सहमति देनी चाहिए।

फैक्ट फटाफट

1. व्हाइट रैबिट (WR)

- यह CERN में संस्थानों और कंपनियों के सहयोग से विकसित एक तकनीक है, जो एक्सेलेरेटर में उपकरणों को उप-नैनोसेकंड तक सिंक्रनाइज़ करने और नेटवर्क में समय की एक आम धारणा स्थापित करने की चुनौती को हल करने के लिए है।
- व्हाइट रैबिट स्विच उप-नैनोसेकंड सिंक्रनाइज़ेशन सटीकता प्रदान करता है, जिसके लिए पहले वास्तविक समय ईथरनेट नेटवर्क के लचीलेपन और मॉड्यूलरिटी के साथ समर्पित हार्ड-वायर्ड टाइमिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। यह ईथरनेट आधारित नेटवर्क में उप-नैनोसेकंड सटीकता प्राप्त करता है।
- व्हाइट रैबिट नेटवर्क का उपयोग केवल वितरित इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को समय और सिंक्रनाइज़ेशन प्रदान करने के लिए, या समय और वास्तविक समय डेटा ट्रांसफर दोनों प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

2. लम्पी स्किन डिजीज

- यह मवेशियों की एक संक्रामक वायरल बीमारी है।
- यह लम्पी स्किन डिजीज वायरस (LSDV) के कारण होता है, जो कैप्रिपॉक्सवायरस जीनस से संबंधित है, जो पॉक्सविरिडे परिवार का एक हिस्सा है (चेचक और मंकीपॉक्स वायरस भी उसी परिवार का हिस्सा हैं)।
- LSDV एक जूनोटिक वायरस नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह बीमारी मनुष्यों में नहीं फैल सकती है।
- भौगोलिक वितरण:
- LSD वर्तमान में अधिकांश अफ्रीका, मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों और तुर्की में स्थानिक है।
- वर्ष 2015 के बाद से यह बीमारी अधिकांश बाल्कन देशों, काकेशस और रूसी संघ में फैल गई है।
- वर्ष 2019 के बाद से, एशिया (बांग्लादेश, भारत, चीन, चीनी ताइपे, वियतनाम, भूटान, हांगकांग (SAR-RPC), नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड) के देशों में LSD के कई प्रकोप सामने आए हैं।

3. न्यायालय की अवमानना

- संविधान के अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय 'रिकॉर्ड न्यायालय' होगा और इसमें ऐसी अदालतों की सभी शक्तियाँ हैं जिनमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है।
- अनुच्छेद 215 ने उच्च न्यायालयों को तदनुरूपी शक्ति प्रदान की गई है।
- न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के अनुसार, न्यायालय की अवमानना या तो सिविल अवमानना या आपराधिक अवमानना हो सकती है।
- सिविल अवमानना का अर्थ है अदालत के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा करना या अदालत को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करना।
- दूसरी ओर, आपराधिक अवमानना का अर्थ है किसी भी मामले का प्रकाशन (चाहे शब्दों द्वारा, बोले गए या लिखित, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा) या कोई अन्य कार्य करना जो कि:
 - किसी न्यायालय के अधिकार को लांछित करता है या लांछित करता है या कम करता है या कम करने की प्रवृत्ति रखता है
 - किसी भी न्यायिक कार्यवाही के उचित पाठ्यक्रम में पूर्वाग्रह, या हस्तक्षेप करता है, या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है
 - किसी अन्य तरीके से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है, या बाधा डालता है या बाधा डालने की प्रवृत्ति रखता है।

4. जापान सागर

- यह पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सीमांत समुद्र है।
- यह पूर्वी एशिया में स्थित है और पूर्व में जापान और सखालिन द्वीप से और पश्चिम में एशियाई मुख्य भूमि पर रूस और कोरिया से घिरा है।
- दोहोकू सीमाउंट, एक पानी के नीचे का ज्वालामुखी, इसका सबसे गहरा बिंदु है।
- समुद्र स्वयं एक गहरे बेसिन में स्थित है, जो पूर्वी चीन सागर से दक्षिण में त्सुशिमा और कोरिया जलडमरूमध्य द्वारा और उत्तर में ओखोटस्क सागर से ला पेरोस (या सोया) और तातार जलडमरूमध्य द्वारा अलग किया गया है।
- पूर्व में, यह कानमोन जलडमरूमध्य द्वारा जापान के अंतर्देशीय सागर और त्सुगारू जलडमरूमध्य द्वारा प्रशांत महासागर से भी जुड़ा हुआ है।
- यह अपने अपेक्षाकृत गर्म पानी के कारण जापान की जलवायु को प्रभावित करता है। यह उत्तर से आने वाली ठंडी धाराओं और दक्षिण से आने वाली गर्म धाराओं के मिलन बिंदु के रूप में कार्य करता है।



5. पुनेट स्कायर

- इसका नाम ब्रिटिश आनुवंशिकीविद् रेजिनाल्ड पुनेट के नाम पर रखा गया है।
- ग्रिड के शीर्ष और किनारे पर, एक तरफ एक माता-पिता और दूसरी तरफ दूसरे माता-पिता के संभावित आनुवंशिक लक्षण सूचीबद्ध हैं।
- फिर, आप प्रत्येक माता-पिता के गुणों को मिलाकर वर्गों को भरें।
- प्रत्येक वर्ग प्रभावी रूप से उन लक्षणों के संभावित संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है जो उनकी संतानों को विरासत में मिल सकते हैं।
- यह संतानों में दिखने वाले विभिन्न लक्षणों की संभावनाओं की कल्पना करने का एक सरल तरीका है।
- इनका उपयोग आमतौर पर जीव विज्ञान में वंशानुक्रम पैटर्न को समझने के लिए किया जाता है, जैसे जब आप स्कूल में प्रमुख और अप्रभावी जीन के बारे में सीखते हैं।
- यह एक उपयोगी उपकरण है जो क्रॉस-ब्रीडिंग के परिणामस्वरूप होने वाली विविधताओं और संभावनाओं की भविष्यवाणी करने में मदद करता है।

प्रीलिम्स ट्रेक

Q1. PMLA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह अधिनियम मनी लॉन्ड्रिंग को केवल काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने के कार्य के रूप में परिभाषित करता है।
2. प्रवर्तन निदेशालय (ED) PMLA के तहत अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार प्राथमिक एजेंसी है।
3. PMLA यह साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर सबूत का बोझ डालता है कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है/हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीनों
- D. कोई नहीं

Q2. निम्नलिखित युग्म पर विचार करें रिपोर्ट : संगठन

1. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट: यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क इंडिया
2. विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट: संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष
3. लैंगिक समानता सूचकांक: यूनेस्को

ऊपर दिए गए जोड़ों में से कितने युग्म सही है/हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीनों
- D. कोई नहीं

Q3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें

1. अधिनियम की धारा 29C के अनुसार सभी राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से अधिक के किसी भी योगदान की घोषणा करना आवश्यक है।
2. यह अधिनियम निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करता है।
3. यह मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया, सीटें भरने के तरीके और मतदाताओं की योग्यता निर्धारित करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है/हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीनों
- D. कोई नहीं

Q4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन I: शरीयत आवेदन अधिनियम मुस्लिम सामाजिक जीवन के पहलुओं जैसे विवाह, तलाक, विरासत और पारिवारिक संबंधों को अनिवार्य करता है।

कथन II: इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्यक्तिगत विवादों के मामलों में, राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार है और एक धार्मिक प्राधिकरण कुरान और हदीस की अपनी व्याख्याओं के आधार पर एक घोषणा पारित करेगा।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- A. कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
- B. कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
- C. कथन I और कथन II दोनों सही हैं और कथन II कथन I की सही व्याख्या है
- D. कथन I और कथन II दोनों गलत हैं और कथन II कथन I का सही व्याख्या नहीं है

Q5. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. वर्ष 2070 तक नेट जीरो हासिल करने के लिए, भारत को परमाणु ऊर्जा को कुछ हज़ार GWe तक बढ़ाने की ज़रूरत है
2. भारत पूरी तरह से स्वदेशी थोरियम-आधारित परमाणु संयंत्र, "भवनी" पर भी काम कर रहा है, जो यूरेनियम-233 का उपयोग करने वाला अपनी तरह का पहला संयंत्र होगा।
3. प्रायोगिक थोरियम संयंत्र "कामिनी" पहले से ही कलपक्कम में मौजूद है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है/हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीनों
- D. कोई नहीं

Q6. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. सार्वजनिक खातों का गठन अनुच्छेद 266 (2) के तहत किया गया था जो उन लेनदेन के लिए प्रवाह का हिसाब रखता है जहां सरकार केवल एक बैंकर के रूप में कार्य कर रही है
2. इससे होने वाले व्यय को संसद द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता नहीं है।

3. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) को भारत सरकार के "सार्वजनिक खाते" में "ब्याज रहित आरक्षित निधि" के अंतर्गत रखा गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है/हैं?

- A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीनों
D. कोई नहीं

Q7. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम (SAIME) पहल शुरू हो गई है।
2. अकेले आंध्र प्रदेश में भारत के झींगा उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा है।
3. भारत दुनिया का सबसे बड़ा झींगा निर्यातक है और इसका सबसे बड़ा आयातक अमेरिका है

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है/हैं?

- A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीनों
D. कोई नहीं

Q8. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. ग्रीन स्टील जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बिना स्टील का निर्माण है।
2. यह अंततः ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है, लागत में कटौती करता है और स्टील की गुणवत्ता में सुधार करता है।
3. RINL-विशाखापत्तनम स्टील प्लांट GHG उत्सर्जन और ऊर्जा खपत को कम करने के लिए अत्याधुनिक क्लीनर प्रौद्योगिकियों को स्थापित करने में अग्रणी रहा है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है/हैं?

- A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीनों
D. कोई नहीं

Q 9. निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

संघर्ष का क्षेत्र: स्थान

1. ताइवान: हिंद महासागर
2. कच्चाथीवू: पाक जलडमरूमध्य,
3. टाइग्रे: उत्तरी यमन

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है/हैं?

- A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीनों
D. कोई नहीं

Q10. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन I: अनुच्छेद 293, जो राज्य को संसद द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर धन उधार लेने की कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है

कथन II: यह संघ को राज्यों को ऋण और गारंटी देने की भी अनुमति देता है, और केंद्र को अपनी सहमति देने और राज्यों पर आगे ऋण जुटाने के लिए शर्तें लगाने की आवश्यकता होती है, जबकि पहले वाले बकाया हैं।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- A. कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
B. कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
C. कथन I और कथन II दोनों सही हैं और कथन II कथन I की सही व्याख्या है
D. कथन I और कथन II दोनों गलत हैं और कथन II कथन I का सही व्याख्या नहीं है

प्रीलिम्स ट्रेक उत्तर

उत्तर : 1 विकल्प A सही है

व्याख्या

- PMLA मनी लॉन्ड्रिंग को अवैध रूप से प्राप्त धन की उत्पत्ति को छिपाने से संबंधित गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में परिभाषित करता है। इसमें प्लेसमेंट, लेयरिंग और एकीकरण चरण शामिल हैं। **इसलिए, कथन 1 गलत है**

- प्रवर्तन निदेशालय PMLA अपराधों के लिए प्राथमिक जांच एजेंसी है। **अतः, कथन 2 सही है**
- PMLA के तहत, कुछ स्थितियों में संदिग्ध संपत्तियों के स्रोत को समझाने का सबूत देने का बोझ आरोपी पर डाला जा सकता है। **इसलिए, कथन 3 गलत है**

उत्तर : 2 विकल्प A सही है

व्याख्या

- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNPF) की इंडिया एजिंग रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत में बुजुर्गों की संख्या 2022 में 149 मिलियन से दोगुनी होकर सदी के मध्य तक 347 मिलियन हो जाएगी।
- बढ़ती उम्रदराज़ आबादी की चुनौतियाँ दशकों दूर हो सकती हैं।
- हालाँकि, युवा देश के लिए उनके लिए पहले से तैयारी करना अच्छा रहेगा।
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) ने विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है।
- **अतः केवल C विकल्प सही है**

उत्तर : 3 विकल्प B सही है

व्याख्या

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 C के अनुसार, वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा संशोधित होने से पहले, सभी राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से अधिक के किसी भी योगदान की घोषणा करने की आवश्यकता थी। **इसलिए, कथन 1 गलत है।**
- चुनावी बांड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1950 के प्रमुख प्रावधान
 - निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करता है। **अतः, कथन 2 सही है।**

- लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं और विधान परिषदों में सीटों के आवंटन का प्रावधान करता है।
- मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया और सीटें भरने की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
- मतदाताओं की योग्यता निर्धारित करता है। **अतः, कथन 3 सही है।**

उत्तर : 4 विकल्प A सही है

व्याख्या

- इसलिए 1937 से, शरीयत एप्लिकेशन अधिनियम मुस्लिम सामाजिक जीवन के पहलुओं जैसे विवाह, तलाक, विरासत और पारिवारिक संबंधों को अनिवार्य बनाता है। अधिनियम में कहा गया है कि व्यक्तिगत विवाद के मामलों में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा
- भारत में शरीयत अनुप्रयोग अधिनियम व्यक्तिगत कानूनी संबंधों में इस्लामी कानूनों के अनुप्रयोग की रक्षा करता है, लेकिन यह अधिनियम कानूनों को परिभाषित नहीं करता है।
- इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्यक्तिगत विवादों के मामलों में, राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा और एक धार्मिक प्राधिकरण कुरान और हदीस की अपनी व्याख्याओं के आधार पर एक घोषणा पारित करेगा। **इसलिए कथन II गलत है**

उत्तर : 5 विकल्प C सही है

व्याख्या

- सरकार देश के अन्य हिस्सों में परमाणु प्रतिष्ठानों के विस्तार को बढ़ावा दे रही है, उदाहरण के लिए, हरियाणा के गोरखपुर शहर में एक आगामी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निकट भविष्य में चालू हो जाएगा।
- भारत पूरी तरह से स्वदेशी थोरियम-आधारित परमाणु संयंत्र, "भवनी" पर भी काम कर रहा है, जो यूरेनियम -233 का उपयोग करने वाला अपनी तरह का पहला संयंत्र होगा। प्रायोगिक थोरियम संयंत्र "कामिनी" पहले से ही कलपक्कम में मौजूद है।
- वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो हासिल करने के लिए, भारत को परमाणु ऊर्जा को कुछ हज़ार गीगावॉट तक बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसा कि आईआईटी-बॉम्बे के विश्लेषणात्मक समर्थन के साथ विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन में सुझाव दिया गया है। **अतः, सभी कथन सही हैं।**

उत्तर : 6 विकल्प C सही है**व्याख्या**

- वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के अधिनियमन के साथ राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (NCCF) का नाम बदलकर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (NDRF) कर दिया गया।
- इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (DM अधिनियम) की धारा 46 में परिभाषित किया गया है।
- इसे भारत सरकार के "सार्वजनिक खाते" में "ब्याज रहित आरक्षित निधि" के अंतर्गत रखा जाता है।
- सार्वजनिक खाते:
- इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत किया गया था।
- यह उन लेनदेन के लिए प्रवाह का हिसाब रखता है जहां सरकार केवल एक बैंकर के रूप में कार्य कर रही है जैसे भविष्य निधि, छोटी बचत आदि।
- ये धनराशि सरकार की नहीं है और इन्हें कुछ समय पर वापस भुगतान करना होगा।
- इससे होने वाले व्यय को संसद द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता नहीं है **अतः, सभी कथन सही हैं।**

उत्तर : 7 विकल्प B सही है**व्याख्या**

- वर्ष 2019 से शुरू होकर, सतत झींगा खेती की समुदाय-आधारित पहल की कल्पना गैर सरकारी संगठनों- नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्डलाइफ सोसाइटी (NEWS) और ग्लोबल नेचर फंड (GNF), नेचरलैंड, बांग्लादेश एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी (BEDS) द्वारा की जा रही है। सस्टेनेबल एकाकल्चर इन मैग्रोव इकोसिस्टम (SAIME) पहल के तहत, किसानों ने पश्चिम बंगाल में 30 हेक्टेयर में झींगा की खेती शुरू की है। **इसलिए, कथन 1 गलत है।**
- अकेले आंध्र प्रदेश में लगभग एक लाख झींगा फार्म भारत के झींगा उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा हैं।
- यह दुनिया का सबसे बड़ा झींगा निर्यातक है और अमेरिकी बाजार में इसकी हिस्सेदारी 21% से बढ़कर 2022-23 में 40% हो गई है, जो थाईलैंड, चीन, वियतनाम और इक्वाडोर जैसे प्रतिद्वंद्वियों से कहीं आगे है। **इसलिए, कथन 2 और 3 सही हैं।**

उत्तर : 8 विकल्प C सही है**व्याख्या**

- RINL-विशाखापत्तनम स्टील प्लांट GHG उत्सर्जन और ऊर्जा खपत को कम करने के लिए अत्याधुनिक क्लीनर प्रौद्योगिकियों को स्थापित करने में अग्रणी रहा है।
- अपशिष्ट ऊष्मा से विद्युत उत्पादन कुल कैप्टिव विद्युत उत्पादन का लगभग 62% है।
- 'प्रत्येक टन इस्पात क्षमता के लिए एक पेड़' के आदर्श वाक्य के साथ, 5 मिलियन से अधिक पेड़ लगाए गए हैं
- ग्रीन स्टील
- यह जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बिना इस्पात का निर्माण है।
- यह कोयला आधारित संयंत्रों के पारंपरिक कार्बन-सघन विनिर्माण मार्ग के बजाय हाइड्रोजन, कोयला गैसीकरण, या बिजली जैसे कम कार्बन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके किया जा सकता है।
- यह अंततः ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है, लागत में कटौती करता है और स्टील की गुणवत्ता में सुधार करता है।
- निम्न-कार्बन हाइड्रोजन (ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन) इस्पात उद्योग के कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद कर सकता है। **अतः, सभी कथन सही हैं।**
- राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन (NHM) स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन विकल्प के लिए हाइड्रोजन का उपयोग करता है।

उत्तर : 9 विकल्प A सही है**व्याख्या**

- ऐवान पश्चिमी प्रशांत महासागर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है, जो चीन, जापान और फिलीपींस से सटा हुआ है। इसका स्थान दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण चीन सागर के लिए एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार प्रदान करता है, जो वैश्विक व्यापार और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। **इसलिए जोड़ी 1 सही ढंग से सुमेलित नहीं है।**
- कच्चाथीवू: यह भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरूमध्य में 285 एकड़ का एक निर्जन स्थान है, जो भारत के रामेश्वरम से लगभग 14 समुद्री मील की दूरी पर स्थित एक द्वीप है।।

- 1974 में, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की सिरिमा आरडी भंडारनायके ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने कच्चातिलु को श्रीलंका के क्षेत्र के हिस्से के रूप में मान्यता दी, जिसके परिणामस्वरूप स्वामित्व में बदलाव हुआ।

अतः जोड़ी 2 सही सुमेलित है।

- टाइग्रे इथियोपिया का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। यह क्षेत्र जातीय क्षेत्रीय मिलिशिया, संघीय सरकार और इरिट्रिया सेना से जुड़े चल रहे नागरिक संघर्ष के केंद्र में है, जिसने नवंबर 2020 से मानवीय समूहों और बाहरी अभिनेताओं की चिंता को आकर्षित किया है। अक्टूबर 2022 में, इथियोपिया सरकार की टीम और टाइग्रे बलों के बीच अफ्रीकी संघ के नेतृत्व वाली पहली औपचारिक शांति वार्ता दक्षिण अफ्रीका में हुई। **अतः जोड़ी 3 सही सुमेलित नहीं है**

उत्तर : 10 विकल्प B सही है

व्याख्या

- अनुच्छेद 293,
- इस विवाद के केंद्र में अनुच्छेद 293 है, जो राज्यों को राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर धन उधार लेने की कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है। **इसलिए, कथन 1 गलत है।**

- यह संघ को राज्यों को ऋण और गारंटी देने की भी अनुमति देता है, और केंद्र को अपनी सहमति देने और राज्यों पर आगे ऋण जुटाने के लिए शर्तें लगाने की आवश्यकता होती है, जबकि पहले के ऋण बकाया हैं।
- केरल का तर्क है कि यह अनुच्छेद केंद्र को सभी राज्य ऋणों को विनियमित करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है और यह केवल केंद्र से उधार लेने पर शर्तें लगा सकता है।
- केरल ने राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा उधार लेने और अपने सार्वजनिक खाते पर देनदारियों को 'नेट उधार सीमा' के तहत शामिल करने के केंद्र के फैसले को भी चुनौती दी है। **अतः, कथन 2 सही है।**
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में 2018 के संशोधन ने 'सामान्य सरकारी ऋण', या केंद्र और राज्य सरकारों के ऋणों का कुल योग, सकल घरेलू उत्पाद के 60% पर सीमित कर दिया।



Mentorship
India

Mentorship India

Our mission is crystal clear – to provide the finest UPSC mentorship and guidance available in India. We recognize that the path to success in the UPSC examination is both demanding and multifaceted. This is precisely why we have developed a comprehensive approach that goes beyond conventional coaching. Our commitment lies in fostering excellence by equipping aspirants with the necessary tools, knowledge, and unwavering support to not only excel in the examination but also in life itself.

Mentorship India represents more than just an organization; it is a community of ambitious individuals bound together by the shared objective of conquering the UPSC examination. We warmly invite you to embark on this transformative journey alongside us. Whether you are a novice taking your initial steps or a seasoned aspirant aiming for the pinnacle, Mentorship India is your dependable companion in the relentless pursuit of excellence.

+91 9999 057869
www.mentorshipindia.com

A-92, Third Floor, Hari Nagar
Delhi - 110064

 @mentorship.india